लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1128

07 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

नई वस्त्र नीति

1128. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः
श्री एन. रेड्डप्पः
श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः
श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का वर्तमान योगदान कितना है;

(ख) क्या सरकार नई कपड़ा नीति 2020 बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने नीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यक्तियों, संघों और राज्यों सहित सभी हितधारकों से पर्याप्त सूचना और सुझाव मांगे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर हितधारकों से क्या प्रतिक्रिया मिली है; और

(ङ) पारंपरिक हथकरघा क्षेत्र के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क). राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2018 के अनुसार भारत की जीडीपी और विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी (प्राथमिक मूल्य पर) में वस्त्र क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमश: 2.01% और 11.22% है।

वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से 45 करोड़ से अधिक लोगों और इस क्षेत्र में नियोजित बड़ी संख्या में महिलाओं तथा ग्रामीण आबादी सहित संबंद्ध क्षेत्रों में और 6 करोड़ लोगों के कार्यरत/नियोजित होने का

अनुमान है। वर्ष 2018-19 के दौरान हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र और अपैरल निर्यात 40.4 यूएस डॉलर था जो भारत के निर्यात का 12% है।

(ख) से (घ). इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक नई वस्त्र नीति तैयार की जा रही है।

सभी राज्य सरकारों, ई-पोर्टल के माध्यम से व्यक्तियों और विभिन्न एसोसिएशनों से इनपुट मंगाए जा रहे हैं। कपास, रेशम, पटसन, ऊन, मानव निर्मित फाइबर, हथकरघा, हस्तशिल्प, विद्युतकरघा, तकनीकी वस्त्र, प्रौद्योगिकी एवं मशीनरी उन्न्यन, अवसंरचना (स्पिनिंग, विविंग एवं प्रोसेसिंग), मानव संसाधन विकास आदि जैसे विस्तृत विषयों पर विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

सभी संबंधित स्टेक होल्डर उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और इनपुट एवं सुझावों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ड़). हथकरघा क्षेत्र का विकास एवं संवर्धन करने तथा हथकरघा बुनकरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय देशभर में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।.

1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
   - (i) ब्लॉक स्तरीय कलस्टर
   - (ii) हथकरघा विपणन
   - (iii) बुनकर बीमा योजना:
   - (iv) हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस):
   - (v) हथकरघा बुनकरों और उनके बच्चों की शिक्षा:
   - (vi) “इंडिया हैंडलूम” ब्रांड
   - (vii) ई-कॉमर्स
   - (viii) शहरी हाट
2) व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)
4) यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत कच्ची सामग्री, करघों और उपस्करों की खरीद, डिजाइन नवीनीकरण, उत्पाद विविधीकरण, अवसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, प्रकाश इकाईयां, हथकरघा उत्पादों का विपणन और रियायती दरों पर ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****